1994. Efforts are being made to obtain it. However, according to the assessment made by the Central Ground Water Board, an apex organisation of the country in the field of ground water, the level of ground water development inLudhiana is 123.16 per cent

(b) The Central Ground Water Board has prepared guidelines for formulation of Artificial Recharge Scheme by the State Government and the drafts manual containing guidelines for formulation of Artificial Recharge Scheme has been circulated by the Board to the State Government.

राष्ट्रीय परियोजनाओं के रूप में घोषित परियोजनायें

6186. श्री कैलाश नारायण सारंग : क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय सरकार द्वारा राष्ट्रीय परियोजनाओं के रूप में घोषित परियोजनाओं की संख्या क्या है ;

(ख) उक्त परियोजनाओं में से कितनी पूरी हो चुकी हैं और उन परियोजनाओं की संख्या क्या है जिनका कार्य अभी चल रहा है ;

(ग) क्या केन्द्रीय सरकार को बाण सागर परियोजनाओं को राष्ट्र हित में राष्ट्रीय परियोजना घोषित किए जाने के संबंध में कोई प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं ;

(घ) यदि हां, तो उक्त प्रस्तावों पर क्या निर्णय लिया गया है ; और

(ङ) यदि कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है तो क्या सरकार बाण सागर परियोजना को राष्ट्रीय परियोजना घोषित करने पर विचार करेगी ?

शहरी विकास मंत्रालय तथा जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी. के. थुन्नन) : (क) सिंचाई क्षेत्र में किसी भी परियोजना को "राष्ट्रीय परियोजना" के रूप में घोषित नहीं किया गया है ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) जी नहीं ।

(घ) प्रश्न नहीं उठता ।

(ङ) केन्द्रीय जल आयोग द्वारा परिकलित व्यापक अवधारणा/मानदण्डों के अनुसार, बाण सागर परियोजना भी राष्ट्रीय महत्व की परियोजना है ।

सरकारी और निजी स्रोतों के द्वारा कृषि योग्य भूमि की सिंचाई

6187. श्री राघवजी : क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 31.3.1994 की स्थिति के अनुसार राज्यवार देश में सरकारी और निजी संसाधनों के द्वारा सिंचित कृषि योग्य भूमि की प्रतिशतता क्या है ;

(ख) क्या केन्द्रीय सरकार उन राज्यों में जिनमें सिंचित भूमि की प्रतिशतता काफी कम है प्रतिशतता बढ़ाने के लिए कोई योजना बनाने का विचार रखती है ; और

(ग) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

शहरी विकास मंत्रालय तथा जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी. के. थुन्नन) : (क) सरकार और निजी स्रोतों से निबल सिंचित क्षेत्र सम्बन्धी अलग-अलग आंकड़े केन्द्रीय सरकार द्वारा नहीं रखे जाते हैं । कृषि मंत्रालय के अद्यतन भूमि प्रयोग सांख्यिकी 1990–91 (अनन्तिम) में दिए अनुसार राज्यवार कुल कृष्य क्षेत्र, कुल निबल सिंचित क्षेत्र तथा कुल कृष्य क्षेत्र में